

करने का सुझाव नहीं देता हूँ और मैं सब को रिक्वेस्ट करूँगा कि यह अहम एमेण्डमेंट होने की वजह से सब लोग मिलकर इसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करें।

[प्रतुवाद]

हम अगली मद पर चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी अब वक्तव्य देंगे।

प्रधानमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वक्तव्य देने में पहले मैं विपक्ष के नेता तथा सभी लोगों के नेताओं तथा अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सब की सर्वसम्मति से इसके माधान का प्रयास किया। मैं उसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ।

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधान मंत्री की नामीबिया यात्रा

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : नामीबिया की आजादी के सिलसिले में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए मुझे 20 और 21 मार्च को विन्डहोक जाने का सुअवसर मिला।

नामीबिया को एक सम्प्रभुतासम्पन्न और स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित होते देखना एवं उसे श्रीमामण्डित एवं आनन्दायक अवसर पर उपस्थित होना—प्रधानमंत्री की हैसियत से अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए इससे अधिक उपयुक्त और कोई अवसर मेरे लिए क्या हो संकेता था। हमने एक ऐतिहासिक समारोह में भाग लिया जो अफ्रीका में उपनिवेशवाद की समप्ति एवं दक्षिण अफ्रीका में शांतिवाद के पलायन का द्योतक था। यह हमारे लिए सचमुच एक अविस्मरणीय अनुभव था।

नामीबिया में हमारे प्रतिनिधिमण्डल जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी, कामरेड सुरजीत, श्री इन्द्रजीत गुप्त, और कांग्रेस (आई) के श्री नारायणन शामिल थे, की उपस्थिति इस बात का प्रमाण था कि जातिवाद एवं उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के प्रति भारत की वचनबद्धता, दलगत एवं विचारगंत श्रेमाओं के परे हैं। यह हमारी मात्र राष्ट्रीय नीति ही नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आजादी की लड़ाई के समय से चली आ रही हमारी राष्ट्रीय मानसिकता का एक अभिन्न अंग है।

मध्य रात्रि के तुरन्त बाद भारत ने नामीबिया के साथ अपना राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया, पहले लगाये गए सभी प्रतिबन्धों को उठा लिया एवं वहाँ एक निवासी हाई कमिशन की स्थापना कर दी। नामीबिया की जनता के, जिसने “स्वापो” के ध्वज के नीचे और राष्ट्रपति सामनुजोमा के नेतृत्व में अपनी आजादी के लिए 23 वर्ष की लम्बी अवधि तक बड़ी वीरता से संघर्ष किया था, इस शक्तिशाली क्षण को हमने भी जिया।

हमें इस बात का गर्व है कि नामीबिया के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देने के जो प्रयास किये जा रहे थे, उनमें भारत पहली पंक्ति में था। हमने “स्वापो” को उसके निर्वासन के दिनों में नैतिक, सामग्रीगत और राजनीतिक समर्थन दिया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व के संक्रमणकाल में भारत ने “संयुक्त राष्ट्र संक्रांति सहायता दल” को एक शांतिरक्षक सैनिक टुकड़ी की सेवाएं, निगरानी के लिए पुलिस की सेवाएं और चुनाव अधीक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराईं। तदन को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि नामीबिया में सेवारत हमारे इन नागरिकों के परिश्रम, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की बहुत सराहना हुई है। मुझे विश्वास है कि हमारे इन नागरिकों की

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

सराहना करने में इस सदन के सदस्य मेरा साथ देंगे। नमीबिया के अनुरोध पर हमने भारतीय पुलिस के 50 मानिटरो को अपने खर्च पर तीन महीने के लिए वहाँ छोड़ना स्वीकार किया है।

राष्ट्रपति साम नुजोमा से अपनी मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें इस बात का वचन दिया कि उनके राष्ट्र-निर्माण के प्रयामों में भारत सहयोग देगा। हमने उन्हें मानव संसाधन विकास एवं नागरिक प्रशासन तथा अध्यापक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएं देने का वचन दिया है। हमने योजना, वित्त एवं जल संसाधन विकास के क्षेत्रों में सलाहकारों की सेवाएं तथा लघु उद्योगों के विकास की संभावनाओं का अध्ययन कराने में अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है हम सामान और सेवा की पूर्ति के लिए उन्हें रियायती ऋण भी देंगे। हमने इन कार्यक्रमों के लिए कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध कराने का इन्तजाम किया है।

नमीबिया की यात्रा के दौरान मुझे फ्रंटलाइन्स स्टेट्स के अध्यक्ष राष्ट्रपति कैनेथ काउन्डा, "अफ्रीकी एकता संगठन" के अध्यक्ष राष्ट्रपति हुसनी मुबारक, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष राष्ट्रपति जानेज द्रोन्वस्क तथा बोत्सवाना के राष्ट्रपति मसिरे, तन्जानिया के राष्ट्रपति म्विन्यी, फिलिस्तीन राज्य के राष्ट्रपति अराफात, मारीशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ और बंगलादेश के प्रधानमंत्री काजी जफर अहमद के साथ उपयोगी विचार-विमर्श का अवसर मिला। अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स बेकर और सोवियत विदेश मंत्री शेवर्दनादजे के साथ भी मेरी लाभप्रद मुलाकातें हुईं। यह एक सुखद संयोग है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पेरेज द कुलियार के साथ मेरी पहली मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई जबकि संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा बायदा पूरा हो रहा था। आप तो जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमीबिया की स्वतंत्रता से पूर्व के संक्रमणकाल में उल्लेखनीय दक्षता और निष्पक्षता के साथ अपना फर्ज अदा किया।

डा० नेल्सन मंडेला के साथ हमारी मुलाकात न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारे प्रतिनिधिमण्डल के सभी सदस्यों के लिए एक अविस्मरणीय एवं मर्मस्पर्शी क्षण था। रंगभेद-विरोधी संघर्ष में सक्रिय भाग लेने की भारत की अटूट परम्परा की, जो महात्मा गांधी की अग्रणी भूमिका से शुरू होकर आज तक बदस्तूर कायम है, उन्होंने हार्दिक प्रशंसा की। लगभग तीन दशक तक कारावास भोगने के बावजूद डा० मंडेला अपने उद्देश्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं; अपने लोगों को रंगभेद से मुक्ति दिलाने में उनका दृष्टिकोण आज भी खंडित नहीं हुआ है; एवं आज भी उनका संकल्प उतना ही दृढ़ है। मैंने एक बार फिर उन्हें सुविधानुसार भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैंने डा० मंडेला को इस बात का भी विश्वास दिलाया कि इस नाजूक दौर में भारत प्रीटोरिया सरकार के खिलाफ लगावे अपने प्रतिबंधों में जरा भी ढील नहीं देगी तथा उस पर यथेष्ट दबाव कायम रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जनमत निरन्तर जागृत करती रहेगी। हम "अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस" के साथ अपनी नीतियों का तालमेल बसाए रखेंगे और रंगभेद को समाप्त करने के संयुक्त प्रयास में, उसे अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन तथा आपके विचारार्थ मैं कुछ ठोस सुझाव प्रस्तुत करूंगा जिनके माध्यम से इस स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है (व्यवधान) विपक्षी दल के नेता ने जो कुछ कहा है, मैं केवल उसका उत्तर दे रहा हूँ (व्यवधान) मेरी बात सुनिए।